years adopting regionally differentiated growth strategies, creation of farming infrastructure and more efficient use of resources.

Financial help to Maharashtra

1265. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Maharashtra Government has sought Centre's financial help to provide relief to farmers in the State;

(b) when a request from the State Government was received in this regard;

(c) whether financial assistance. has been provided; and

(d) if not, by when it is likely to be provided?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (d) In his letter dated 16th November, 1998 to the Prime Minister, the Chief Minister of Maharashtra has requested for an assistance of Rs. 300 crore for natural calamities that occurred during 1997-98. The State Government has also submitted a memorandum seeking Central assistance of Rs. 152 crore in the wake of heavy rains/floods during June to October, 1998. The request is under examination for suitable action.

दलहनों की प्रति –व्यक्ति उपलब्धता

1266. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)दलहनों की वर्तमान प्रति-व्यक्ति उपलब्धता कितनी हैं; खाद्य तथा कृषि संगठन के मानकों के अनुसार यह मात्रा आवश्यकता की तुलना में कितनी हैं;

(ख)क्या अगले तीन वर्षो में देश की खपत को ध्यान मे रखते हुए इसके अंतर की कोई कल्पना की गई है और उस दृष्टि से बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या उपचारी योजनाएं बनाई गई हैं;

(ग)क्या इस दृष्टि से, उत्तर प्रदेश मे दलहनों की पैदावार बढ़ाने की कोई योजना हैं; और

(घ)यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (**श्री सोम पाल**) : (क) पिछले तीन वर्षो के लिए देश में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता इस प्रकार होने का अनुमान हैं:-

वर्ष	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (कि. ग्राम प्रतिवर्ष)
1996	12.0
1997	14.0
1998	12.8

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के संस्तुत पोषणिक मानकों के अनुसार किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने वाले व्यक्ति के लिये कम लागत वाले संतुलित आहार मे दालों की आवश्यकता 40 ग्रामम प्रतिदिन है जो 14.60 कि.ग्रा प्रति वर्ष बैठती है। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा निर्धारि दालों की न्यूनतम आवश्यकता के प्रतिमानों संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ) किसी भी समय के लिए दालों की सही-सही आवश्यकता का अनुमान लगाना कठिन हैं क्योंकि मांग विभिन्न कारकों पर निर्भर करती हैं यथा उत्पादन स्तर, अन्य विकल्पों की उपलब्धता, आय, जनसंख्या और खाने-पीने की आदतें। वैसे, कृषि, जिंसों की मांग और पूर्ति के पुर्वानुमानों संबंधी कार्य दल ककी रिपोर्ट और नौवीं पंच वर्षीय योजना के निरूपण हेतु कृषि आंकड़ों में सुधार के अनुसार, 2001-2002 के लिए दालों के उत्पादन की आवश्यकता, 7 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर 19.50 मिलियन मीटरी टन तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद की सिफारिश अनुसार प्रतिमानिक आवश्यकता 17.20 मिलियन मीटरी टन होगी। 2001-2002 के लिये दालों का सर्वाधिक संभावित पूर्ति पूर्वानुमान 17.50 मिलियन मीटरी टन का हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा 26 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जिनमे उत्तर प्रदेश भी शामिमल हैं, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही हैं।

इस योजना में प्रमाणित बीजों, बीज मिनिकिटों

राईजोबियन कल्चर, सूक्ष्म पोषक तत्वों उन्नत कृषि उपकरणों पौध रक्षण उपकरणों आदि के उत्पादन और वितरण के लिएए राज्यों को वित्तीय सहायता देना प्रतिपादित है। इसके अलावा, उन्नत दलहन उत्पादन प्रौद्योगिक के प्रभावी अंतरण के लिए खेतों में प्रदर्शनों तथा कृषक प्रशिक्षणों का आयोजन भी किया जाता हैं।

Measures to give Impetus to Agriculture Sector

1267. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what special mesures Government have so far taken to give inpetus to Agriculture sector;

(b) whether Government have decided to revamp SFAC (Small farmers Agro Business Consortium) which was set up six years ago, as reported in the Hindustan Times, dated the 7th November, 1998; and

(c) what steps Government have taken, so far, to save the farmers from the price volatility due to the vagaries of nature, indicating also whether private investment in the agriculture sector is being allowed by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) During the 9th Five Year Plan which is being finalised. Government is proposing to enhance the allocation for the Agriculture Sector and is committed to double the food production in the next 10 years. For this purpose, a number of Central/Centrally Sponsored Schemes arc being implemented.

.(b) Yes, Sir.

(c) The Government is fixing the Minimum Support Price (MSP) for' as many as 24 commodities and also has a Market Intervention Scheme for the purpose. Besides, a new comprehensive crop insurance scheme is being evolved. There is no bar on private investment in agriculture and a number of companies are engaged in producing seeds, fertilisers, machinery etc.

कृषि की नई तकनीकों का किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव

1268. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क)क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले दो दशकों में किसानों की आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन में भारी कमी आई है और है और वें कृषि की नई तकनीकों को अपनाने के बाद रासायनिक खादों, बाहरी बीजों और उपकरणों पर बहुत अधिक निर्भर हो गए हैं और कृषि पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है और महंगी तकनीकों अपनाने के बाद किसान अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख)यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम जा रहे हैं; और

(ग)यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सोम पाल) : (क) से (ग) किसानों के लिए उनकी उत्पादकता, उत्पादन तथा बढ़ाने हेतु उपयुक्त उत्पादन तथा संरक्षण प्रौद्योगिकण का विकास, सरकार के लिए अत्याधिक चिन्ताजनक रहा है। देश के विभिन्न तथा उनके समक्ष आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर स्वदेशी प्रौद्योगिक का विकास करने को, सभी फसल सुधार कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जाती हैं।

विशेषकर अधिक उपज देने वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरकों का उपयोग अनिवार्य्र हैं। मृदा विश्लेषण पर आधारित सिफारिशों के अनुसार जब इसका प्रयोग किया जाता हैं, तो मृदा पर इसके किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना किसानों को लाभकारी आय प्राप्त होती हैं। यंत्रीकरण से भी, बहु-फसलन तथा प्रयुक्त आदनों की बेहतर प्रतिक्रिया के तरीके से कृषि की पैदावार में वृद्धि होती हैं।

देश में चावल गेहूं, मक्का, सौरघम, बाजरा आदि जैसी फसलों के लिए बहुत सी संकर किस्में विकसित की गई हैं जिनसे किसानों को अधिक लाभ पहुंचा हैं।

सरकार की नीतियों के परिणामस्वरूप, पिछले पचास वर्षो मे फसल उत्पादन मे लगभग चार गुना वृद्धि हुई हैं। इसिलिए, किसानों की आत्म-निर्भरता में किसी प्रकार के हास का प्रश्न ही नहीं उठता।